SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: In the country during 1988-89.

SHRI VASANT SATHE: In the country? Yes, there are quite a few stations.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Manguru has got some of the best coal mines and specially coal is available at the surface itself. As the hon. Minister has pointed out, open cast mines can come up very easily and very well. This will be the cheapest supply of the coal in the country. Under the circumstances, keeping in view that electricity has to be organised as a grid, why should not priority be given and the work undertaken immediately?

SHRI VASANT SATHE: Sir, this is a suggestion. We will consider this suggestion also.

MR. CHAIRMAN: Question No. 422.

Availability of Cooking Gas Facility at Block Centres in States

*422. SHRI LAL K. ADVANI:†
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to answer to the Starred Question 33 given in the Rajya Sabha on the 9th November, 1987 and state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for making available cooking gas at block centres in various States especially in the tribal and hilly areas; if so, what are the out-lines thereof; and if not, what are the reasons therefor;

(b) the State-wise number of such block centres where this facility is already available; and

(c) the State-wise targets fixed for the current year and the next year in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) While there is no proposal to make the LPG facility available at Block Headquarters as such including such centres in the tribal and hilly areas, LPG marketing is being extended by the Oil industry in a phased manner to locations with a population of around 20,000 and above and offering sufficient potential for economically viable distributorships;

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha;

(c) Does not arise in view of part (a) above.

SHRI LAL K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, before I put my question I would like to point out to you that while Government has always the right in certain cases to say that the information is being collected and it will be laid on the Table of the House as soon as possible, in this particular case, the information that is being sought is such that it should be readily available with the Ministry here; it is not a State subject.

Even in the first part of the question, the reply given is: "LPG marketing is being extended by the oil industry in a phased manner to locations with a population of around 20,000 and above". Such phased planning of the whole programme would necessarily entail that they must be knowing the State-wise targets fixed in the current year and the next year in this regard. So I fail to understand how in a matter of this kind it can be said that the information is to be collected, it should all be available here. Sir, this is a way only of evading the question. In a question of this kind I expected the Minister to give us the basic facts about the number of places because there is not a large number of places where LPG facilities are available It is very limited; it should be much more than it is. Nevertheless, having pointed this out, I would

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lal K. Advani.

like to draw attention to a statement by the Minister made sometime back in Simla where he said that there was no shortage, either of cylinders, or of regulators, or of gas. There was no shortake of any kind. The bottleneck lay in the paucity of bottling plants. May I ask in this regard that if this is the position, then what is the crash programme for setting up bottling plants that the Government has undertaken and by what time do we hope to acquire self-sufficiency in so far as LPG is concerned? That is my first question.

SHRI BRAHM DUTT: About the first part of hon. Member's observations, I would like to submit that there are about 5000 block headquarters and this information is being collected within the oil industry from among ourselves as to how many block headquarters we have surveyed and how many we have not surveyed. About distributorships, in 1980-81, the number was 1104, in 1983-84, 1812 and in 1986-87, 3071. This year we hope to increase it to 3320. About the other part of the question, it is a fact that we have got natural gas and we have got enough capacity to manufacture cylinders and regulators. We are increasing the bottling capacity. At present the bottling capacity is 13,88,000 metric tonnes per annum. We have got 46 bottling plants throughout the country. We are setting up 42 new bottling plants and this will create an additional facility for 7,78,500 metric tonnes per annum and I hope this will be completed by 1988 in various phases. In 1988 the third phase will be over.

SHRI LAL K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, some time back, I understand, a committee headed by an honourable Member of this House, Shrimati Sudha Joshi, had been set up by the Government. I believe that that committee has submitted its recommendations to the Government. What are the principal recommendations of this committee and what is the Government's response thereto?

SHRI BRAHM DUTT: Sir, the report has been submitted only two, three weeks back. It is being studied. I am also going through it and very soon, I think in the next session, we will give our opinion or comments and what we propose to do about it. Only very recently it has been submitted.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईंधन की जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते है, विशेषकर पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में और जब तक उन्हे दूसरा ईंधन न दिया जाए उनसे यह आशा करना कि वे वनों की रक्षा करेंगे व्यावहरिक नही होगा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैस आपूर्ति में पर्वतीय और वनवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी? अभी जो उत्तर दिया है उसके अनुसार तो 20,000 आबादी वाले क्षेत्रों तक आप गैस पहुंचा रहे है। अब इतनी बड़ी संख्या में एक स्थान पर पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रो में लोग रहते हो ऐसा नही दिखाई देता। क्या सरकार यह नीति संबंधी निर्णय करेगी कि जब सब चीजे हो जाएंगी, बोटलिंग-प्लांट हो जाएगा गैस तो है ही पहले से तो प्राथमिकता दी जाएगी वनवासी और पर्वतीय क्षेत्रो को जिसमे साथ-साथ वनो का भी सरक्षण हो सके?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर मै माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हू और इसके लिए बोटलिंग कैपेसिटी हो जाएगी उसकी भी प्रतीक्षा नही की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रो मे हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि हर पर्वतीय क्षेत्र में कश्मीर में, हिमाचल मे, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल कुमाऊं मे, नार्दन ईस्टर्न रीजन मे छोटे बोटलिंग प्लाट जल्दी लगा लें। लेकिन इसके अलावा एक हमने और सुविधा दी है, 20 हजार की आबादी पर एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप स्थापित की जाती है, उसके अलावा उस डिस्ट्रीब्यूशनशिप को एक्सटेंशन पाइंट भी एलाऊ करते हैं। दिक्कत उसमे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज की आ रही है। थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा,

थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो यह काम हमने शुरू कर दिया है। राजस्थान और दूसरे जो ऐसे क्षेत्र है, जहां हमको जगल बचाने हैं या जगल के आसपास के क्षेत्र है, उनकी भी हमने एक लिस्ट बनाई है और उसको प्राथमिकता के आधार पर जो वहा का बेकलोग है, उसको कम करने के लिए नई जगह स्थापित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए पहले से कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूर्णतया सहमत हू और इसके ऊपर हमने कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति जी, मैं मत्री जी से यह रिपोर्ट के बारे मे जानना चाहूगा कि कब तक, निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे? दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रो मे विशेष रुचि लेकर उनमे जो वह कार्यरत है, उनको कब तक, जल्दी से जल्दी दिलाने के लिए कोई अवधि मुकर्रर कर सकते है?

श्री ब्रह्म दत्त . मान्यवर, मैंने रिपोर्ट के बारे मे यह निवेदन किया कि दो-तीन सप्ताह पहले वह रिपोर्ट हमें मिली है। मै उम्मीद करता हूं कि जनवरी तक हम उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लेगे और अगले अधिवेशन में माननीय सदन को हम अवगत् करा सकेंगे। यह जो आदिवासी क्षेत्र और जगल के क्षेत्र के बारे में है, माननीय वाजपेयी ज ने पूछा था, मैं उनका उत्तर दे चुका हू। हम इसके ऊपर कार्यवाही कर रहे है और सन् 1988 में हमारी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, यह सारे प्लाट हमारे कमीशन हो जाएगे और हम प्राथमिकता उन जगहो को देगे, जहा हम जगलो को बचा सके और वैकल्पिक इंधन की वहा व्यवस्था कर सके।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, पेट्रोलियम विभाग के इस गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सबंध मे जितना कम कहा जाए, उतना ही अच्छा है। महोदय, अभी मत्री जी ने बहादुरी से कहा कि हमारे पास गैस है और सब चीज है, लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीलरशिप के बारे में...

श्री सभापति आप प्रश्न कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मै प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन इसके बैकग्राउंड मे कुछ जरूरी बाते कहना चाहता हू।

श्री सभापति . इस संबध मे हमारे पहले के चैयरमेन ने कुछ नियम बना दिए है, आप उनका ध्यान रखिए।

श्री राम अवधेश सिंह . इनके मंत्रालय की जो गैस देने वाली कपनियां है, जैसे—इंडियन आइल कार्पोरेशन वगैरह वे इनको गलत सूचना देती हैं।

श्री सभापति क्या वह आपको गलत सूचना देती है। यह तो प्रिविलेज मोशन बना सकता है।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, माननीय सदस्य ने कभी ऐसी शिकायत नही की।

श्री राम अवधेश सिंह महोदय, मैंने दो बार कहा है।

श्री सभापति आप सवाल पूछिए।

श्री राम अवधेश सिंह मैं पूछ रहा हू। महोदय, मैं डीलरशिप के बारे में पूछना चाहता हू कि जो नीति सरकार ने तय की है, उसमे शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए डीलरशिप की पूर्ति होती है? और क्या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे है? क्योंकि हरिजन-आदिवासियों को जो डीलरशिप दी जाती है, उसे रद्द करने के लिए आफिसर मिलजुल...

श्री सभापति . आपके दो मिनिट हो चुके है।

श्री राम अवधेश सिंह : अभी नही हुए है।

श्री सभापति मेरे सामने घडी रखी हुई है।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय मै जानना चाहता हू कि डीलरशिप के लिए जो नीति तय है उसका पालन मंत्री जी करते है? और बाटलिंग के जो प्लांट्स है उनका कितना खर्च है और क्या उसे पूरा करने मे दिक्कत हो रही है और मैंने जयश्री एंटरप्राइजेज के बारे में लिखा था, उसके बारे मे इन्होने क्या कार्यवाही अभी तक की है?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए जहां तक गैस एजेंसी का सवाल है, यह कास्टिट्यूएन्सी के हिसाब से प्रदान की जाती है। अगर शेडयूल्ड कास्ट के लिए है तो उसे दी जाती है और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है तो उसे दी जाती है।

श्री राम अवधेश सिंह : उनका परसेंटेज आप उनको दे पा रहे है?

श्री ब्रह्म दत्त : उनके अलावा किसी को नहीं दी जा सकती है। दूसरा प्रश्न आपका बाटलिंग प्लाट का है। उनके लिए पैसे का पूरा प्रावधान हमारे पास है। अगर कोई ऐसी शिकायत है कि किसी तरह मे किसी की डीलरशिप गलत तरीके से कैंसिल की जा रही है या उसे परेशान किया जा रहा है तो उसे मै स्वयं देख सकता हू।

श्री राम अवधेश सिंह : **

श्री सभापति : श्री जगतपाल सिंह ठाकुर अब आप प्रश्न पूछिए। जो अवधेश सिंह जी पूछ रहे है, वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

ठाकुर जगतपाल सिंह : सभापति महोदय, जो प्लाट लगाए जा रहे है, उसमें जगह का क्रायटेरिया क्या है?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, साधारणतः कोई विशेष क्रायटेरिया नहीं है सिर्फ ट्रांसपोर्ट का क्रायटेरिया है। कहा मे सुविधा रहेगी--ट्रेस या रोड से ले जाना पड़ता है।

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 87-88 में लगभग 3320 डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर दी जाएगी। उन्होने यह भी बताया कि कुल 5 हजार ब्लाक हैडक्वार्टर्स, 5 सौ जिला हैडक्वार्टर्स और 24 स्टेट हैडक्वार्टर्स हैं। लगभग 5524 ऐसे केन्द्र है। कई शहरो मे ज्यादा एजेंसिया भी होगी तो लगभग दो-ढ ई हजार एजेंसियां है। जितने आप बाटलिंग प्लाट्स लगा रहे है तो अब प्लानिंग में कोई कमी है। क्योंकि गैस की कमी नही, धन की कमी नही, सिलेंडर की कमी नही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से, एनर्जी कंजर्वेसन की दृष्टि मे जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि जंगल बेतहासा काटे जा रहे है, उन्हे रोका जाना है। उसको ध्यान मे रखते हुए आप कब तक हर ब्लाक हैडक्वार्टर्स तक देने की योजना बना सकते है?

श्री ब्रह्म दत्त : यह कहना तो मुश्किल होगा कि कब तक हर ब्लाक हेडक्वार्टर पर यह हो सकता है। कमी उन्ही चीजो की है जिनका कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। लेकिन कमी एक चीज की और है। एक गैस कनेक्शन लेने के लिये एक आदमी को एक हजार रुपये की पूंजी लगानी पड़ती है, हॉट प्लेट आदि सब को मिला कर और अगर वह दो सिलेंडर लेता है तो उस को सवा सौ रुपये ईधन पर खर्च करना पडता है और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जिन को बायो गैस इस एल पी जी से ज्यादा सस्ती पडती है। तो एक तरफ [illegible] गैस का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रहे है क्योकि वह सस्ती पडती है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि जहा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है वहा उन से गुणात्मक डिस्ट्रीब्यूशन हो और जैसे जैसे इस की उपलब्धि बढती जायेगी हम इसको बढ़ाते जायेंगे। दस साल तक हम ब्लाक लेविल पर पहुंच सकते है और आठ सालों मे भी पहुंच सकते है।

श्री भगतराम मनहर : माननीय सभापति महोदय, पर्वतीय क्षेत्रों मे रहने वाले

**Not recorded.

जलावन लकड़ी जंगलो मे प्राप्त कर लेते है और वर्तमान मे रसोई गैस का दाम 60 रुपया या उसके करीब है। वहां पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालो की इतनी आमदनी नही है कि वे इस गैस को खरीद सकें, उन मे भी आदिवासी खास कर। और जो योजना है उस के मुताबिक अगर आप ने डीलरशिप दे दी तो वह उस को खरीदने की स्थिति मे नही रहेंगे और उन की स्थिति ज्यो की त्यो रहेगी। इस को मीट आउट करने के लिए आप के पास क्या योजना है कि आप उन को सस्ते में गैस दिला सके, रसोई गैस।

श्री ब्रह्म दत्त : उपभोक्ता गैस जो है उस में सब्सीडी की मात्रा पहले ही अधिक है उस पर कुछ और दाम कम करने में मुश्किल पडेगी और पूरी अर्थ-व्यवस्था पर इस का असर पडेगा। लेकिन विचार किया जा सकता है प्रदेशीय सरकारों के साथ कि जहां जहां डीलर्स हैं वहां से गावों तक गैस पहुंचाने के लिए यदि वे कुछ मदद कर सकें या उस का कुछ और इंतजाम कर सकें निगमो आदि के जरिये तो साधारणत: ऐसा हो सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जो मंत्री जी का उत्तर है वह इस बात का प्रमाण है कि पर्वतीय क्षेत्रो के लोग और आदिवासी क्षेत्रो के लोग जो आरोप लगाते हैं केन्द्र सरकार पर और प्रदेश की सरकारो पर कि हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है और उत्तराखंड के लोगो ने — इसके लिये बडा एक विशाल प्रदर्शन किया है, उस को देखते हुए मेरा आप से प्रश्न है कि जो जनसंख्या की सीमा आप ने 20,000 कर रखी है तो उन लोगो के साथ कोई भेदभाव और कोई पक्षपात न हो इसके लिये इस जनसख्या की सीमा को घटा कर क्या आप 5000 करने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नही हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग ऐसा कोई आरोप लगाते हैं। मैं खुद पर्वतीय क्षेत्र का हूं। हां, बाहर के लोग उन से आरोप लगवाते जरूर हैं, ऐसा मै मानता हूं। लेकिन जनसंख्या की सीमा 5000 करना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नही होगा। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रो के लिये और ऐसे दूरस्थ इलाकों के लिये मैंने निवेदन किया था कि एक्सटेंशन प्वांइट हम रख रहे हैं। डिस्ट्रिब्यूटरशिप दे दी गयी है लेकिन वह 20-25 मील के क्षेत्र में गैस सप्लाई कर सकते हैं इसके लिये कोई पाबन्दी नही है।

Establishment of Ancillary units at Korba and Singrauli

*423. SHRI AJIT P.K. JOGI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the work relating to the establishment of ancillary units of thermal power stations at Korba and Singrauli has not yet been taken up by the National Thermal Power Corporation Limited;

(b) if so, what action Government propose to take to ensure that the ancillary units are set up expeditiously and additional job opportunities created for the local people; and

(c) what are the reasons that the NTPC has not implemented the guidelines issued by the Bureau of Public Enterprises in this context?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Standing Committee of Small Scale Industries Board of Ancillary Development have categorized the N.T.P.C. as an enterprise with very limited or no scope of ancillarisation. The spare parts required in the operation of super thermal plants are largely procured from the suppliers of main plant equipment. How-